

भाग – दो: खण्ड एक
तेंदू पत्ते का राष्ट्रीय
व्यापार
अध्याय 1

मध्यदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (वर्ष
1964 का 29)

दिनांक 23 नवम्बर, सन् 1964 को राष्ट्रपति की अनुमित प्राप्त हुई जो “मध्यदेश राजपत्र, (असाधारण)” दिनांक 28 नवम्बर, 1964 को प्रकाशित की गई - तेन्दू पत्तों के व्यापार को लोकिहत में विनियमन करके, और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु अधिनियम:

भारत गणराज्य के पन्निहवें वर्ष में मध्यदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावे:
धारा 1. संक्षिप्त नाम व विवतार तथा प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम मध्यदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 कहलावेगा।

(2) इसका विवतार क्षेत्र पूरा मध्यदेश होगा।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में, या क्षेत्रों में तथा ऐसे दिनांकों को प्रवृत्त होगा, जिसे या जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उल्लेखित करे।

नोट - यह अधिनियम पूरे मध्यदेश में दिनांक 28-11-64 से प्रवृत्त हुआ जिसकी अधिसूचना म.प्र. शासन वन विभाग के नोटीफिकेशन ब. 14334/x/64 दिनांक 28 नवम्बर, 1964 द्वारा जारी हुई जो दिनांक 28 नवम्बर, 1964 से राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ ब. 3368 पर प्रकाशित हुई।

धारा 2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) अभिकर्ता (Agent) से तात्पर्य धारा “4” के अधीन नियुक्त किये गये अभिकर्ता से है।

(ख) संहिता (Code) से तात्पर्य “मध्य प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959” (भूराज:व संहिता, 1959) (वर्ष 1959 का 20) से है।

(ग) व्यापारी से तात्पर्य कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, कम्पनी, निवभाजित हिन्दु परिवार या सोसायटी (जिसमें सहकारी सिमित सिमिलित है) क्लब, भ्रमर, एसोसियेशन, कमीशन एजेंट, या अन्य वाणिज्यिक एजेंट से है जो तेन्दूपत्ता खरीदने, बेचने और प्रदाय करने का व्यापार सीधे सीधे या अन्य प्रकार से करता है, चाहे नगदी, में आन्तर्गत भुगतान में, या कमीशन मजदूरी या फलितफल से करें।

(घ) “तेन्दू पत्ता उगाने वाला” (Grower of Tendu Leaves) से तात्पर्य -

(i) उन क्षेत्रों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (ब. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के रूप में गिठित किये गये क्षेत्र में, उगे तेन्दू के पौधों के सम्बन्ध में राज्य शासन से हैं।

(ii) उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाए गये तेन्दू के पौधों के सम्बन्ध में -

1. म.प्र. अधिनियम ब. 1 वर्ष 2008 द्वारा संशोधित।

(a) राज्य शासन है, जहां तेन्दूपत्ता संहिता की धारा (2) के खण्ड ‘ब’ में परिभाषित दिखल रिहत भूमि पर उगाया जावे।
(ब) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले ऐसे खाते के यथास्थित भूधारी या भाड़ेदार, या शासकीय पट्टाधारी या ऐसी सेवा भूमि के धारक से, है जिसमें तेन्दू के पौधे उगते हों, और उसमें ऐसा व्यक्त सिमिलित है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो।

(स) किसी ऐसी इकाई में जिसमें तेन्दू पत्ता उगते हों, यथास्थित मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 (ब. 15 वर्ष 1953) के अधीन भूदान धारक, मध्य-भारत भूदान यज्ञ विधान, 1955 (ब. 3, वर्ष 1955) के अधीन भूदान कृषक या भूदान पट्टेदार, विध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1955 (ब. 1, वंज्र 1956) के अधीन भूदान कृषक, तथा राज:थान भूदान यज्ञ एक्ट, 1954 (ब. 16, वर्ष 1954) के अधीन अनुदान महीता से है और उसमें ऐसा व्यक्त सिमिलित है जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो।

(ड) “खाता से तात्पर्य -

(एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराज:व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो भूमि स्वामी द्वारा धारित हो, और (दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में, एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शतों के अधीन यथास्थित भूमि:वामी या राज्य शासन से धारण किए गए भूमि खण्ड से है।

(च) “सेवा भूमि के धारक” से तात्पर्य गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूधारण करने वाले व्यक्ति से है।

(छ) “शासकीय पट्टेधारी” से तात्पर्य संहिता की धारा 181 के अधीन राज्य शासन से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है।
छछ निमाता- से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति (बीड़ी मजदूर के अतिरिक्त) स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, निवभाजित हिन्दु परिवार, या सोसायटी (जिसमें सहकारी सोसायटी सिमिलित है) क्लब, फर्म, या एसोसियेशन, जो बीड़ी बनाने के कार्य में लगी हो बेचा है किसी भी तरीके से बीड़ी बनावे।

(ज) “उल्लिखित क्षेत्र” (Specified Area) से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र से है।

(झ) “भाड़ेदार” (Tenant) से तात्पर्य संहिता के चैदहवें अध्याय के अधीन भूमि ंवामी से मौरूसी काँतकार के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है।

(ण) “भूधारी” (Tennure holder) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य शासन से भूमि धारण करता हो और जो संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि ंवामी हो या भूमि ंवामी माना गया हो।

(ट) “इकाई” (Unit) से तात्पर्य उल्लिखित क्षेत्र के उस उप-खण्ड से है जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गिठत किया गया हो।

1. म.पू. अधिनियम ब. 1 वर्ष 2008 द्वारा छछ जोड़ी गई।

(ठ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में यूयोग में लाई गई हो, किन्तु पिरभाषित न की गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (ब. 16, वर्ष 1927) में पिरभाषित की गई हों, का वही तात्पर्य होगा जो उनके लिये उस अधिनियम में दिया है।

धारा 3. इकाईयों का गठन - राज्य शासन लूत्येक उल्लिखित क्षेत्र को उतनी इकाईयों में विभाजित कर सकेगा जितनी कि वह उपयुक्त समझे।

धारा 4. (1) राज्य शासन, अपनी ओर से तेन्दू पत्तों के बय तथा व्यापार के हेतु विभिन्न-विभिन्न इकाईयों के लिये अभिकतार्ओं की नियुक्ति कर सकेगा तथा कोई भी ऐसा अभिकतार् एक से अधिक इकाईयों के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) अभिकतार्ओं की नियुक्ति सम्बन्धी निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावें -

धारा 5. तेन्दू पत्ते के बय या पिरवहन पर निबन्धन - (1) किसी भी क्षेत्र में धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन सूचना जारी होने पर -

(क) राज्य शासन।

(ख) इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये शासन के किसी पदाधिकारी, या

(ग) जिस इकाई में पत्ते उगाये गये हों उस इकाई से सम्बन्धित अभिकतार् को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति तेन्दू पत्तों का न तो बय करेगा और न पिरवहन करेगा।

व्याख्या 1. (एक) राज्य शासन या पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी, या अभिकतार् द्वारा धारा 12 A के अन्तर्गत किया गया तेन्दू पत्तों का बय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया बय नहीं समझा जावेगा।

(दो) खाते में कोई विहत न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने कि ऐसे खातों में उगाये गये तेन्दू पत्तों का संमह करने का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसे पत्तों का बय किया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तिवर्ष किसी बात के होते हुए भी -

(क) तेन्दू पत्ते को उगाने वाला, अपने पत्तों का पिरवहन, ऐसी इकाई के भीतर, जिसमें तेन्दू पत्ते उगे हों, किसी ंथान से उस इकाई में किसी ंथान तक कर सकेगा और,

(ख) “ऐसे तेन्दू पत्तों का, जिनका बय राज्य शासन से तथा उक्त उपधारा में उल्लिखित किये गये किसी पदाधिकारी या अभिकतार् से किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बीडियों के निमार्ण के लिये या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर विबय के लिये धारा 5 के संशोधन जो म.पू. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 7 वर्ष 1989 द्वारा किये गये हैं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इकाई के बाहर पिरवहन उस सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकार द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी फीस की देनगी की जाने पर, जैसा कि विहित किया जाये, जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्र के निबन्धों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की पिरवहन गाडियों के लिये फीस की विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी।”

1. धारा 4 एवं 5 के संशोधन म.पू. तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम (7 वर्ष 1989) द्वारा किये गये। राजपत्र दिनांक 17-4-89 पृष्ठ 739-41

(3) तेन्दू पत्ते का विबय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उन्हें पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी या अभिकतार् को इकाई के भीतर ंथत किसी भी संमहागार (फड़) में बेंच सकेगा।

नोट - अधिसूचना ब. 6505/ख/65- मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार) विनियम, 1964 की धारा 5 की उपधारा 1 (ख) अनुरूप राज्य शासन सभी वन अधिकारियों को, जो कि वनपाल के पद के नीचे के न हों, तथा संभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) के पद के उच्च पद के न हों, उन्हें इस नियम के अन्तर्गत तेन्दू पत्ता खरीदने एवं थानान्तरित करने का अधिकार प्रदान करता है।

(म.पू. राजपत्र असाधारण दि. 26.5.65, पृष्ठ 1915)

टिप्पणी - (1) खरीददार को एक इकाई से बाहर दूसरी इकाई पर तेन्दू पत्ता ले जाने के लिये अनुज्ञिप्त की आवश्यकता है, इसी प्रकार उपरोक्त न्याय दृष्टान्त में यह भी स्तिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 5(2) ब के ावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11(1) (फ) तथा (ज) का उल्लंघन नहीं करते।

(देखें - बृजलाल मिणलाल एण्ड कं. वि.म.०. राज्य-M.P.L.J. 1966 पृष्ठ 866, J.L.J. 1966, पृष्ठ 963)

(2) धारा 5 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या 301 का उल्लंघन नहीं होता।

देखें - M.P.L.J. 1967 पृष्ठ 267, J.L.J. 1967 पृष्ठ 569 A.I.R. 1967, M.P. 218, M.P.L.J. 1966 पृष्ठ 2 लाल राधो शा वि.म.०. राज्य)

(3) तेन्दू पत्ते के व्यापार में तेन्दू पत्ता बय करना तथा बेचने का व्यवहार सिम्मिलत है तथा खरीदे गये पत्तों का पिरवहन व्यवहार में नहीं आता।

देखें - M.P.L.J. 1970 पृष्ठ 129 में बृजलाल मिणलाल कम्पनी वि. म.०. राज्य)

(4) तेन्दू पत्ते का एकाधिकार, राज्य के भीतर उगे पत्तों से है तथा राज्य के बाहर से पत्ता लाने पर स्तिबन्ध नहीं है याचिकाकर्ता राज्य के बाहर से तेन्दू पत्ता लाकर अपने कारोबार के ंथान पर एकित करता है तब धारा 5 का उल्लंघन नहीं करता।

(देखें - म.०. राज्य वि. में छोटा भाई जेठा भाई पटेल एण्ड कं. 1972 M.P.L.J. पृष्ठ 641 (सु.को.) (ii) A.I.R. 1968 M.P.

127)

(5) बीड़ी िनमार्ताओं को खरीदी गई इकाई से अपने गोदाम या शाखा तक तेन्दूपत्ता पिरवहन करने के लिए अनुज्ञिप्त की आवश्यकता है लेकिन ऐसे पत्तों को मजदूरों को बीड़ी बनाने हेतु देने के लिये अनुज्ञिप्त की आवश्यकता नहीं है।

(देखें - बृजलाल मिणलाल एण्ड कं. वि. म.०. राज्य - M.P.L.J. 1970 पृष्ठ 518)

धारा 6. लुप्त।

धारा 7. राज्य शासन मूल्य िनधारित करेगी: राज्य शासन, तेन्दूपत्ता उगाने वालों का तेन्दूपत्ता, उसके द्वारा, अधिकृत अधिकारी द्वारा या एजेन्ट द्वारा, राज्य शासन के अतिरिक्त खरीदने का मूल्य, उस विधि से जो िनधारित की जावे, िनधारित करेगी।

1. तेन्दू पत्ता व्यापार विनियम संशोधन अधिनियम 2007 (1 वर्ष 2008) को धारा 4 द्वारा धारा 6 विलोपित तथा धारा 7 ितःथापित।

धारा 8. संमहागारों का खोला जाना तथा संमहागारों (फड़ों) पर मूल्य सूची आद का ाकाशन - ात्येक इकाई में ऐसी संख्या में तथा ऐसी ंथानों पर, जैसा कि राज्य शासन, तेन्दू पत्ता उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए िनर्देशित करे, संमहागार (फड़ें) ंथापित किए जायेंगे और धारा 7 के अधीन राज्य शासन द्वारा िनिश्चित की गई तेन्दू पत्तों की मूल्य सूची, काम-काज के घण्टे, उस सूचना-फलक पर ामुख रूप से संूदिशर्त किए जायेंगे जो कि इस ायोजन के लिए ात्येक ऐसे संमहागार में रखा गया हो।

धारा 9. राज्य शासन या अभिकर्ता तेन्दू पत्तों का बय करेगा - (1) राज्य शासन या उसका ाधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता, काम-काज के घंटों के भीतर, संमहागार (फड़) में विबय के, लिए ातुत किए गए तेन्दू पत्ते, धारा 7 के अधीन िनिश्चित किए मूल्य पर, खरीदने को बाध्य होगा:

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन ाधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा, उसके पत्तों के अवीकार कर िदए जाने के कारण पिरवेदित (Aggrieved) कोई भी व्यक्ति, ऐसी अवीकृति के पन्हिदिन के भीतर, ऐसी इकाई पर िजसमें कि पत्ते उगे हों क्षेाधिकार रखने वाले वन मण्डलाधिकारी या इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा सशक्त किए गये अन्य पदाधिकारी को मामला िनिर्दष्ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन िशकायत ाप्त होने पर, यथािथित वन मण्डलाधिकारी, या ऐसा अन्य पदाधिकारी, उसी ंथान पर या मुख्यालय पर विहित रीति से जांच करेगा और सम्बन्धित पक्षों या उनके ाधिकृत अभिकर्ता को सुनने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब वह पत्तों को अवीकार करना अनुचित पाता हो।

(क) यदि वह ाश्राधीन पत्तों को अब भी बीडियों के िनमार्ण के लिए उपयुक्त समझता हो, यथािथित पदाधिकारी या अभिकर्ता को उसका बय करने के आदेश दे सकेगा और पिरवेदित व्यक्ति (Aggrieved person) को ऐसा अमेतर स्तिकर (Further compensation), जैसा कि वह उचित समझे, और जो उसे पत्तों के देय मूल्य के बीस स्तिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए िनर्देश दे सकेगा।

(ख) यदि वह समझे कि ाश्राधीन (in question) पत्ते, इस बीच बीड़ी के िनमार्ण के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं तो पिरवेदित व्यक्ति को ऐसी रकम जो कि उपधारा (1) के अधीन, उसको ऐसे पत्तों के देय मूल्य से कम न हो, तथा ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठाई

गई हांन के िलए क्षितपूितर् धन के रूप में ऐसा अमेतर ूितकर, जैसा िक वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य के बीस ूितशत से अधिक न हो, भुगतान के िलए िनदेश दे सकेगा।

(4) इस धारा की िकसी बात का यह अथर् नहीं िलया जायेगा िक यिद राज्य शासन, उसके ूाधिकृत अधिकारी या अभिकतार् को यह िवश्वास करने के कारण हो िक िवबय के िलये ूतुत िकये गये पत्ते, राज्य शासन के वनों या भूमियों के हैं, तो ऐसे पत्तों को अधिकार में लेने और केवल ऐसे संमहण सम्बन्धी व्ययों के, यिद कोई हों, जैसे िक राज्य शासन समय-समय पर अवधारित करे, भुगतान करने में कोई रुकावट आती है:

िकन्तु िकसी िववाद की दशा में, वन मण्डलाधिकारी या ऐसा अन्य पदाधिकारी, जो िक उपधारा (2) में उल्लिखित िकये गये रूप में इस सम्बन्ध में िविशष्ट रूप से सशक्त कर िदया जावे, उसमें उपबंथित रीति में उसे सुनेगा तथा उसका िनपटारा करेगा।

नोट - मध्य ूदेश शासन अधिसूचना ब. 247/x/65 िदिनांक 12-1-65, राज्य शासन म. ू. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन), 1964 (ब. 29, वषर् 1964 की धारा 9 की उपधारा (2) से ूदत्त शिक्तियों द्वारा समतः पिरक्षेऽ अधिकारियों (Range Officers) को उक्त धारा (9) के उपधारा (2) के अधिकारों का ूयोग करने के िलए सशक्त करता है।

धारा 10. रिजःशीकरण - राज्य शासन को छोड़कर, तेन्दू पत्तों का अन्य उगाने वाला, यिद यह संभावना हो िक वषर् के दौरान, उसके द्वारा उगाये पत्ते का पिरणाम, ऐसे पिरणाम से जो िविहत िकया जावे, अधिक हो जावेगा, ंवयं को िविहत रीति से रिजःशीकृत करा लेगा।

धारा 11. बींडियों के िनमार्ता और तेन्दूपत्ता व्यापारी का रिजःशीकरण - (1) ूत्येक बींडियों का िनमार्ता तथा ूत्येक तेन्दू पत्ते का व्यापारी, जैसे कालाविध के भीतर जो िनधारित की जावे और ऐसी फीस का भुगतान कर और उस िविध से जो िनधारित की जावे, ंवयं को रिजःशीकृत करावेगा।

(2) बींडियों का ूत्येक िनमार्ता और तेन्दू पत्ते का ूत्येक व्यापारी को उपधारा (1) में रिजःशीकृत िकया गया हो, ऐसे ूारूप में, ऐसे िदिनांक तक ऐसी रीति से जो िविहत की जावे, घोषणा ूतुत करेगा।

धारा 12. पत्तों का िनवर्तन - इस अधिनियम के अधीन, राज्य शासन द्वारा या उसके पदाधिकारी या अभिकतार् द्वारा बय िकये तेन्दू पत्ते ऐसी रीति में, जैसा िक राज्य शासन िनदेश दे, बेच िदये जावेंगे या उनका अन्यथा िनवर्तन कर िदया जायेगा।

धारा 12.क. अतिरिक्त तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय - (1) कोई बींडियों का िनमार्ता या तेन्दू पत्तों का िनयार्ता, िजसके पास उसकी आवँयकता { } के पश्चात् अतिरिक्त माऽ में तेन्दू पत्ता बचा रह जाता हो, वह ऐसे अतिरिक्त बचे तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय राज्य शासन की या ऐसी िकसी पदाधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में ूाधिकृत िकया जाए, अनुज्ञा के िबना नहीं करेगा। वह व्यिक्त, जो ऐसे तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय करने का अभूय रखता हो, राज्य शासन अथवा ूाधिकृत अधिकारी को ऐसे ूारूप में, ऐसी िविशष्टयां अन्तिवर्ष करते हुए, जैसा िक िविहत िकया जाए, आवेदन करेगा।

(2) कोई बींडियों का िनमार्ता या तेन्दू पत्तों का {व्यापारी} जो इस धारा की उपधारा (1) में विणर्त तेन्दू पत्तों में ऐसे अतिरिक्त पिरणाम का बय करने का अभूय रखता हो, उसका बय राज्य शासन की या ऐसी िकसी ूाधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में ूाधिकृत िकया जाए, अनुज्ञा के िबना नहीं करेगा। ऐसा बींडियों का िनमार्ता या तेन्दू पत्तों का {व्यापारी} राज्य शासन को या ऐसे िकसी पदाधिकारी को, जो इस सम्बन्ध में ूाधिकृत िकया जाए, ऐसे ूारूप में, ऐसी िविशष्टयां अन्तिवर्ष करते हुए जैसा िक िविहत िकया जाए, आवेदन करेगा।

(3) तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय करने के उपधारा (1) के अधीन आवेदन तथा ऐसे तेन्दू पत्तों का बय करने के िलए उपधारा (2) के अधीन आवेदन ूाप्त होने पर, राज्य शासन या ूाधिकृत पदाधिकारी बेता द्वारा ऐसी रांश की, जो िक िविहत की जाए, देनगी की जाने पर, उन दोनों को िलिखत में अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पणी - धारा 12, 19-धारा 12 के शब्द “िनदेश दें” का तात्पर्य यह नहीं िक राज्य शासन िनयम नहीं बना सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन का तेन्दू पत्तों के िवबय के, िविनियमन के या िनवर्तन के िनयम बनाने की पूणर् शिक्त है। धारा 19 के अन्तर्गत राज्य शासन को िनयम बनाने की शिक्त ूाप्त है।

(देखें A.I.R. 1966 M.P. 34 (39))

1. म. ू. तेन्दूपत्ता व्यापार विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2007) ब. 1 वषर् 2008) द्वारा धारा 11 पुनः ंथापित। धारा 12 A संशोधित।

धारा 12. तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 - राज्य द्वारा कितपय इकाईयों से तेन्दू पत्ता िवबय के िलये िनिवदायें आमंित की गई तथा याचिकाकतार् द्वारा िनिवदा ूतुत की गई एवं ूतिभूति रांश जमा की गई। िकन्तु िनिवदा खुलने के पूवर् याचिकाकतार् द्वारा िनिवदा वापस लेने का आवेदन िदया तथा अनुरोध िकया िक िनिवदा न खोली जावे। िकन्तु िनिवदा खोली गई क्योंकि वह अकेली थी। याचिकाकतार् द्वारा इकरारनामा िनपांदिता नहीं िकया। पश्चात् तेन्दू पत्ते का िवबय अन्य व्यिक्त को िकया गया तथा याचिकाकतार् द्वारा दी गई िनिवदा तथा बाद में बेचे गये तेन्दू पत्तों का िवबय मूल्य के अंतर की रांश की वसूली की कायर्वाही की गई। िनणर्य हुआ िक िनिवदा सूचना की शतेर् जो धारा 12 के

अन्तर्गत रूकाशित हुई, विविध का रूप नहीं ले सकती संविदा जो संविधान की धारा 299(1) के अनुसार निरूपित नहीं की गई, रूभावशाली नहीं हैं।

देखें: (1) M.P.L.J. D1966, पृष्ठ 1057

(2) M.P.L.J. 1972 पृष्ठ 648

राजेन्डि कुमार वमार् वि. म. रू. राज्य

J.L.J. 1972, पृष्ठ 345

A.I.R. 1972 M.P. 131

इसी रूकार यदि संविधान की धारा 299(1) के अनुसार संविदा निरूपित न हो तो राज्य शासन हाइन की राशि, धारा 82 (भा.व.अ. 1927) के अन्तर्गत वसूल नहीं कर सकता। (राम जुड़ावन तितवारी वि. वन संरक्षक भोपाल, वी. नो. 1980(1), पृष्ठ 303)

तेन्दू पत्ते के संग्रहण हेतु निविदा बुलाई गई किन्तु रूवीकृत नहीं सूचित की गई। शासन हाइन नहीं वसूल कर सकता। 1987 M.P.L.J./102

धारा 13. शक्तियों का रूत्यायोजन (Delegation of Power) - राज्य शासन, आदेश द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सहायक वन संरक्षक से निम्न रूेणी के किसी भी पदाधिकारी या रूाधिकारी को अपनी किन्हीं भी शक्तियों से या कृत्यों से रूत्योजित (delegate) कर सकेगा जो कि उन्हें ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन, जैसी की राज्य शासन आदेश में उल्लिखित करे, रूयोग में लायेगा या सम्पादित करेगा।

नोट - राज्य शासन ने निम्नानुसार अधिकार दिये हैं।

अधिसूचना ब. 246/X/65 दिनांक 12-1-65 मध्य रूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (ब. 29, वर्ष 1964) की धारा 13 द्वारा रूदत्त शक्तियों का रूयोग करते हुए राज्य शासन, निम्न अनुसूची के रूतम्भ (Column 2) में रूदिशर्त अधिकारों को इन्हीं अनुसूची के रूतम्भ (Column 3) में रूदिशर्त अधिकारियों को अधिकार रूदत्त करता है जो कि तत्त अनुसूची के रूतम्भ 4 में निरर्देशित यदि कोई शर्त या रूतिबन्ध हो तो उसको मानते हुए कि तत्त अधिकारों का रूयोग करेगा।

(म.रू. राजपऽ दिनांक 12-1-1965, पृष्ठ 34 पर रूकाशित)

अनु. 1	अधिकार 2	अधिकारी 3	शर्त एवं रूतिबन्ध	रिमाक रू
1. 2. 3.	अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इकाई गठन का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभिकर्ता-कताओं की नियुक्ति का अधिकार तथा अभिकर्ताओं की नियुक्ति को रूद्द करने की शक्ति अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत डिपो खोलने का अधिकार	1. वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, भोपाल। 2. मुख्य वन संरक्षक, म.रू. भोपाल। 3. उप मुख्य वन संरक्षक, म.रू. भोपाल। क्षेत्रीय वृत्तों के रू भारी वन संरक्षक संभागीय वन अधिकारी (वन मण्डलाधिकारी)	राज्य सरकार की पूर्ण अनुमित से अधिकार का रूयोग होगा	अधिसूचना ब. 618-X-71 रूदि 18-2-71 द्वारा संशोधित रूतिबन्ध म.रू. शासन वन विभाग की अधिसूचना ब. 974/X/(2)-70 रूदि. 14-4-70 जो राजपऽ दिनांक क 21-4-70 पर पृष्ठ 915-916 पर रू काशित से

धारा 14. अधिहरणीय सम्पत्ति के अभिग्रहण की शक्ति और उसके लिये रूबिया - (1) समस्त वन पदाधिकारी या सहायक उप-निरीक्षक से अनिम्र रूेणी का कोई भी पुलिस पदाधिकारी या राज्य शासन द्वारा रूाधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से या रूवयों का यह समाधान करने की दृष्टि से उक्त उपबंधों का पालन किया गया है -

(एक) तेन्दू पत्ते के िलये उपयोग में लाये गये या उपयोग में लाये जाने के िलये अभूित िकसी नाव, गाड़ी या तेन्दू पत्ता भरने के िलये उपयोग में लाया जाने वाला सामान (भक्कू) को रोक सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा।

(दो) िकसी ंथान में ूवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) तेन्दू के उन पत्तों का िजनके सम्बन्ध में यिद संदेह को िक इस अधिनियम के अधीन या उसके बनाये िनयमों के िकसी उपबन्ध का उल्लंघन िकया है, िकया जा रहा है, िकया जाने वाला है, तो वह सामान, िजसमें पत्ते रखे हों या पत्तों को ले जाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली गािडियों या नाव सहित अभिमहण कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन िकसी सम्पित्त का अभिमहण करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति, िजसे राज्य शासन ने इस सम्बन्ध में ूाधिकृत िकया हो, ऐसी समःत सम्पित्त पर यह उपदिशत करने वाला एक िचन्ह लगायेगा िक उसका इस ूकार अभिमहण िकया गया है, और अभिमहीत की गई सम्पित्त को या तो यथाशक्य शीय सहायक वन संरक्षक से अनम्र ैणी के पदाधिकारी के या िकसी ऐसे व्यक्ति के िजसे राज्य शासन ने, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में ूाधिकृत अधिकारी िनयुक्त िकया हो, (जो इसमें इसके पश्चात् ूाधिकृत पदाधिकारी के नाम से िनिदर्ष्ट है) समक्ष पेश करेगा, या जहां पिरणाम या ूपुंज (बल्क) को, अन्य वाःतिवक किठनाई को ध्यान में रखते हुए यह साध्य न हो िक अभिमहीत की गई सम्पित्त को ूाधिकृत पदाधिकारी के समक्ष पेश िकया जा सके, वहां वह अभिमहण की बाबत ूितवेदन ूाधिकारी को करेगा, या जहां अपराधी के िवरूद्ध दािण्डक कायर्वाहियां तुरंत आरम्भ करना अभूित हो, वहां ऐसे अभिमहण का ूितवेदन उस मिजःशेट को करेगा जो उस अपराध का िवचारण करने की अधिकािरता रखता हो िजसके िक कारण अभिमहण िकया गया है।

परंतु जब वे तेन्दू पत्ते िजनके बारे में ऐसा अपराध िकये जाने का िवश्वास िकया जाता है, शासन की सम्पित्त है, और अपराधी अज्ञात है, तब यिद पदाधिकारी पिरिःथितियों के बारे में ूितवेदन अपने पदीय विरष्ठ को यथाशीय दे देता है तो वह पर्याप्त होगा।

13.A (1) कोई वन अधिकारी, जो वन क्षेऽ पाल के पद से अनम्र पद का न हों और िजसके अधीनःथ अधिकारी ने उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई औजार, नाव, वाहन रःसी चेन या अन्य वःतु जप्त की हो, को उन वःतुओं के मािलक द्वारा, उन वःतुओं के मूल्य मािलक, द्वारा उन वःतुओं के मूल्य के बराबर या उस अधिकारी की सन्तुष्टि तक की रािश की जमानत िनंपादित की हो और यह िलिखत में, यह बन्ध पऽ ूःतुत करे िक वह उन वःतुओं को िजस ंथान पर, िजस िदनांक को िनदेर्िशत िकया जावे, ूाधिकृत अधिकारी या उस मिजःशेट के सामने, िजसको, उस ूकरण की सुनवाई की अधिकािरता है, ूःतुत करेगा, सुपुदर्गी में दे सकेगा।

(4) उपधारा (6) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, जब ूाधिकृत पदाधिकारी का यथािःथित तेन्दू पत्तों को अपने समक्ष पेश िकये जाने पर या अभिमहण के बारे में ूितवेदन के ूाप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है िक उसके बारे में अपराध िकया गया है, तो वह, िलिखत आदेश द्वारा, अभिलिखत िकये जाने वाले कारणों से, उन तेन्दू पत्तों को, जो इस ूकार अभिगृहीत िकये गये हैं, समःत औजारों, गािडियों, नावों, रःसों, जंजीरों या िकन्हीं अन्य वःतुओं सहित, िजनका िक उपयोग ऐसे अपराध के करने में िकया गया है अधिहृत कर सकेगा। (ूाधिकृत अधिकारी के आदेश की एक ूित) असम्यक् िवलम्ब के िबना उस वृत्त के वन संरक्षक को भेजी जायेगी िजसमें िक तेन्दू पत्तों को अभिगृहीत िकया गया है।

(5) उपधारा (3) के अधीन िकसी संपित्त को अधिहृत करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं िकया जायेगा जब तक िक ूाधिकृत पदाधिकारी –

1. म.ू. तेन्दू पत्ता व्यापार िविनयम संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा उपधारा 3-A जोड़ी गई तथा 4 में संशोधन िकया।

(क) सम्पित्त के अधिहरण के िलये कायर्वाहियां शुरू िकये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का, िजसके कारण अभिमहण िकया गया है, िवचारण करने की अधिकािरता रखने वाले मिजःशेट को िविहृत ूारूप में नहीं भेज देता।

(ख) उस व्यक्ति को, िजससे यह सम्पित्त अभिगृहीत की गई है तथा िकसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, िजसके बारे में ूाधिकृत पदाधिकारी को यह ूतीत होता हो िक उसका ऐसी सम्पित्त में कोई िहित है, िलिखत सूचना नहीं दे देता।

(ग) खण्ड (ख) में िनिदर्ष्ट व्यक्ति को ूःतावित अधिहरण के िवरूद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा िक सूचना में िलिखत िकया जाये, अभ्यावेदन करने का अवसर दे देता; और

(घ) अभिमहण करने वाले पदाधिकारी की तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की, िजसे उन्होंने खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी हो सुनवाई, उस ूयोजन के िलये िनयत िकये जाने वाले िदनांक को नहीं कर लेता।

(6) उपधारा (4) के अधीन, िकन्हीं औजारों, गािडियों, नावों, रःसों, जंजीरों या िकसी अन्य वःतु के (जो अभिगृहीत िकये तेन्दू पत्तों से िभन्न हो) अधिहरण का कोई आदेश नहीं िकया जायेगा यिद उपधारा (2) के खण्ड (ख) में िनिदर्ष्ट कोई व्यक्ति, ूाधिकृत पदाधिकारी के समाधानूद रूप में यह सािबत कर देता है िक िकन्हीं ऐसे औजारों, गािडियों, नावों, रःसों, जंजीरों या अन्य वःतुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के िबना िकया गया था और यह िक इस अधिनियम के

अधीन िकसी अपराध के िकये जाने के िकये पूर्वोक्त वःतुओं के उपयोग को रोकने के िलये समःत युक्तियुक्त और आवँयक पूर्वार्धानियां बरती गई थीं।

(7) इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली तलाशी एवं जप्त के सम्बन्ध में, भा.द.०. संहिता 1973 (ब. 2 1974) को धारा 102 एवं 103 के तलाशी एवं जप्ती के ूावधान, जहां तक लागू हों, इसमें भी लागू होंगे।

18. जब उस ूाधिकृत अधिकृत द्वारा, िजसका उस क्षेऽ पर क्षेऽाधिकार हो, उसने ःवयं वःतुएं जप्त की हो या िजसने उस ू करण का अन्वेषण िकया हो, तो वन मण्डलाधिकारी उस ू करण को उसी पद के दूसरे अधिकारी को हःतांतरित कर सकेगा जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

14. क. अधहरण के आदेश के िवरूद्ध अपील - (1) अधहरण के िकसी आदेश से पिरवेदित कोई व्यक्ति, आदेश के िलए िकये जाने के िदनांक से तीस िदन के भीतर, या यदि ऐसे आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने के िदनांक से तीस िदन के भीतर, उस वन वृत्त के, िजसमें तेन्दू पत्ते अभिगृहीत िकये गये हों, वन संरक्षक (जो इसमें इसके पश्चात् अपील ूाधिकारी के नाम से िनिर्दष्ट है) को िलिखत में अपील कर सकेगा िजसके साथ ऐसी फीस जमा की जायेगी और जो ऐसे रूप में देय होगी जैसा िक िविहित िकया जाए, और उसके साथ अधहरण के आदेश की ूमाणित ूति संलग्न होगी।

(2) उपधारा (1) में िनिर्दष्ट अपील ूाधिकारी, उस दशा में जबिक उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, अभिमहण करने वाले {पदाधिकारी} को, और ऐसे िकसी अन्य व्यक्ति को, िजसका िक अपील अधिकारी की राय में ूाधिकृत अधिकारी के आदेश से ूितकूलतः ूभावित होना संभाव्य है, (िजसके अन्तर्गत अपीलाधीर, यदि कोई हो, आता है) ःवूरेणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई की सूचना {ूाधिकृत अधिकारी} के आदेश की ूति उसे ूाप्त होने के िदनांक से तीस िदन के भीतर ःवूरेणा से दे सकेगा, और अपील के ज्ञापन के पेश िकये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्तियों को देगा, और मामले के अभिलेख मंगा सकेगा।

परंतु अपील की कोई औपचारिक सूचना अपीलाधीर, अभिमहण करने वाले पदाधिकारी और ऐसे िकसी अन्य व्यक्ति िजसका िक पूर्वोक्तानुसार ूितकूल, ूभावित होना संभाव्य है, में से उसको िदया जाना आवँयक नहीं होगा जो सूचना अधित्यजन कर दे या िजसे अपील की सुनवाई का िदनांक, अपील ूाधिकारी द्वारा िकसी अन्य रीति में सूचित िकया जा सकता हो।

1. म.०. तेन्दूपत्ता व्यापार िविनयमन संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा उपधारा '8' जोड़ी गई। 14 'क' (2) में संशोधन िकया।

(3) अपील अधिकारी, अपील िकये जाने की, या ःवूरेणासे की जाने वाली कार्यवाही िकये जाने के बारे में में ूाधिकृत अधिकारी को िलिखत सूचना देगा।

(4) अपील अधिकारी, अधहरण की िवषय वःतु की अभिरक्षा पिररक्षण या व्ययन (यदि आवँयक हो) के िलये अन्तिरम ःवरूप ऐसे आदेश पािरित कर सकेगा जैसे िक उसे उस मामले की पिरिःथितयों में न्यायसंगत ूतीत हो।

(5) अपील अधिकारी, मामले की ूकृति या अन्तर्गत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका ूतिनिधित्व उनके अपने िविध व्यावसायियों के द्वारा िकये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या ःवूरेणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के िलए िनयत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, िजसके िलए सुनवाई रखी जावे, अपील अधिकारी अभिलेख का पिरशीलन करेगा और यदि अपील के पक्षकार ःवयं उपिःथत हों तो उनकी सुनवाई करेगा या िलिखत में सम्यक रूप से ूाधिकृत िकये गये िकसी अभिकतार् या िविध व्यवसायी की माफर्त सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपान्तिरत करने का आदेश पािरित करने के िलए अमसर होगा, परन्तु कोई आदेश पािरित करने के पूर्व अपील अधिकारी यदि अपील के या ःवूरेणा से की गई कार्यवाही के उचित िनपटारे के िलये, यह आवँयक समझा जाता है तो अतिरिक्त जांच या तो ःवयं कर सकेगा या ूाधिकृत अधिकारी से करवा सकेगा और िकसी ऐसे तथ्य का, जो िवचारथर् उद्भूत हो, ूाख्यान या खण्डन करने के िलए पक्षकारों को शपथ पऽ फाइल करने के िलये अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों का सबूत शपथ पऽ द्वारा िकये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील ूाधिकारी पािरणािमक ःवरूप के ऐसे आदेश भी पािरित कर सकेगा जैसे िक वह आवँयक समझे।

(8) अंतिम आदेश की, या पािरणािमक ःवरूप के आदेश की ूति पालन के िलये अपील ूाधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पािरित करने के िलये, ूाधिकृत पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

धारा 14. ख. अपील ूाधिकारी के आदेश के िवरूद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण - (1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील ूाधिकारी द्वारा पािरित िकये गये अंतिम आदेश से या पािरणािमक ःवरूप के आदेश से पिरवेदित हो, उस आदेश के, िजसके िवरूद्ध आक्षेप िकया जाना ईप्सत है, तीस िदन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को,

पुनरीक्षण के िलये याचिका ूःतुत कर सकेगा िजसके सेशन खण्ड के भीतर अपील ूाधिकारी का मुख्यालय िःथत हो।

1. म.०. तेन्दूपत्ता व्यापार िविनयमन संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा उपधारा '8' जोड़ी गई। 14 'क' (2) में संशोधन िकया।

व्याख्या - इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालाविध की संगणना करने में, वह समय अपविजर्त कर दिदया जायेगा जो अपील ूाधिकारी के आदेश की ूमाणिता ूति अभूत करने के िलए अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील ूाधिकारी द्वारा पारित किये गये किकसी अंतिम आदेश या किकसी पारिणामिकःवरूप के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, या उसे उपात्तरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये आदेश की ूतियां, अपील ूाधिकारी को तथा ूाधिकृत पदाधिकारी को, पालन के हेतु या ऐसे अतिरक्त आदेश पारित करने हेतु या ऐसी अतिरक्त कायर्वाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा किक ऐसे न्यायालय द्वारा िनदेशित किकया जाये।

(4) इस धारा के अधीन किकसी पुनरीक्षण को महण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विविनिश्चत करने के िलये सेशन न्यायालय, जहां तक हो सके उन्हीं अधिकारों का ूयोग करेगा और उसी ूबिया का अनुसरण करेगा िजसका किक ूयोग और अनुसरण वह दण्ड ूबिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन किकसी पुनरीक्षण को महण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विविनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड ूबिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तिवर्ष किकसी तत्तूितकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किकया गया सेशन न्यायालय का आदेश अंतिम होगा और किकसी भी न्यायालय के समक्ष ूश्रगत नहीं किकया जायेगा।

धारा 14. ग. कितपय परिःथितयों में न्यायालय आद की अधिकािरता का वर्जन - (1) उस अपराध का, िजसके कारण उस सम्पित का, जो किक अधहरण की विषय-वःतु है, अभिमहण किकया गया है विचारण करने की अधिकािरता रखने वाले मिजःशेट को सम्पित के अधहरण के िलये कायर्वाहियां शुरू की जाने के बारे में धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन सूचना के ूाप्त होने पर, किकसी भी न्यायालय, अधकरण या ूाधिकारी (जो यथाःथित धारा 14, 14-क में िनिदर्ष्ट ूाधिकृत पदाधिकारी, अपील पदाधिकारी तथा सेशन न्यायालय से िभन्न हो) को, इस अधिनियम में या तत्समय ूवृत्त किकसी अन्य विविध में अन्तिवर्ष किकसी बात के होते हुए भी, उस सम्पित के कब्जे, पिरदान, िनवर्तन या विवरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकािरता नहीं होगी िजसके बारे में धारा 14 के अधीन अधहरण की कायर्वाहियां शुरू हो गई हैं।

परन्तु सम्पित के िनवर्तन के िलए कोई आदेश पारित करने के पूर्वर, मिजःशेट अपना यह समाधान कर लेगा किक धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को या उस अपराध का िजसके कारण सम्पित का अभिमहण किकया गया है, विचारण करने की अधिकािरता रखने वाले किकसी अन्य न्यायालय को ूाप्त नहीं हुई है।

व्याख्या - जहां तत्समय ूवृत्त किकसी विविध के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने की अधिकािरता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहां ऐसी अधिकािरता रखने वाले मिजःशेट के न्यायालयों में से किकसी एक को धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन की सूचना ूाप्त हो जाने पर यह अथर् लगाया जायेगा किक उस उपबंध के अधीन सूचना समःत न्यायालयों पर ूवितर्त होगी।

(2) इसमें इसके पूर्वर अन्तिवर्ष किकसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा किक वह राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में ूाधिकृत किकये गये किकसी पदाधिकारी को इस बात से िनवारित करती है किक वह धारा 14 अधीन अभिगृहीत की गई किकसी सम्पित को तुरन्त िनमुर्क्त किकये जाने का िनदर्श किकसी भी समय दें।

धारा 14. घ. सम्पित का अधहरण, जब किक वह उपज शासन की सम्पित न हो - ऐसे समःत तेन्दू पत्ते, जो दोनों में से ूूयेक दशा में शासन की सम्पित नहीं है और िजसके विषय में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के किकसी उपबंध का उल्लंघन किकया गया है, तथा समःत औजार, नावें, गािडियां, रःसे, जंजीर या कोई अन्य वःतुएं, िजनका ूूयेक दशा में उपयोग ऐसा उल्लंघन करने में किकया गया है, अपराध को ऐसे उल्लंघन के िलये दोषिसद्ध ठहराये जाने पर धारा 14-14-क, 14-ख तथा 14-ग के अधधीन रहते हुए अधहरणीय होगी।

नोट - वन विभाग, भोपाल अधि. ब. एफ 18-3-87 दस दिनांक 6.1.90: म.०. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (ब 29 वर्ष 1964) की धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा ूदत्त शिक्तियों को ूयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, समःत सहायक वन संरक्षक, जो उप वनमण्डल के ूभार में हों, को उक्त धारा में िनिहत ूयोजन के िलए ूाधिकृत अधिकारी घोषित करता है।

नोट - मध्य ूदेश शासन वन विभाग अधिसूचना ब. 248/X/65 दि. 12.1.65 - मध्यूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (ब. 29, वर्ष 1964) का धारा 14 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ूदत्त शिक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन सभी वन अधिकािरियों को उनके सम्बिन्धत अधिकार-क्षेऽों के िलये किथत धारा के ूयोजनों के िलये अधिकृत करती है।

धारा 15. शाःत - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के किकन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो -

(क) वह कारावास से िजसकी अविध तीन मास से कम न हो तो जो एकवर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या अथर्दण्डसे जो पांच हजार रूपये िसे कम न हो और जो रूपये 50,000 तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

जब तक किक न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो किक सजा से भी न्याय की मांगकी पूितर् हो जावेगी और वह उन कारणों को लेखबद्ध करेगी।

(ख) उन तेन्दू पत्तों को, जिनके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, या उनके ऐसे भाग को, जैसा कि न्यायालय को उचित लगे हो, शासन के पक्ष में जप्त कर लिया जायेगा:

परंतु यदि न्यायालय की राय है कि यथास्थित सम्पूर्ण पत्तों या उनके किसी भाग के सम्बन्ध में जप्ती का निर्देश देना आवश्यक नहीं है, तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर, ऐसा नहीं करेगा।

धारा 16. चेष्टाएँ तथा अभूँषण (Attempt and abetment) - किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध का उल्लंघन करने की चेष्टा करे, या उसके उल्लंघन को अभूँषित (abets) - करे, ऐसे उपबन्ध का उल्लंघन करने वाला समझा जावेगा।

धारा 17. अपराधों का रूसंज्ञान (Congizance) - खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) से अनिवार्य किसी वन पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो कि इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा रूपाधिकृत कर दिया जावे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, किये गये लिखित रूपाधिकृत के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का रूसंज्ञान नहीं करेगा।

नोट - राज्य शासन व विभाग की अधिसूचना ब. 249/X/65 दि. 12-1-65 से सभी सहायक वन संरक्षकों को तथा ब. 8772/X/69 दि. 20-12-1969 से सभी अतिरिक्त सहायक वन संरक्षकों को धारा 17 के रूपाधिकृत के लिये रूपाधिकृत किया है। किन्तु राज्य शासन ने अब अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक का पद नाम भी सहायक वन संरक्षक कर दिया है। पहली अधिसूचना राजप5 (असाधारण) दि. 12-1-65 के 12-1-65 के पृष्ठ 34 पर तथा दूसरी मध्यदेश राजप5 (असाधारण) दि. 22-12-1969 के पृष्ठ 2941 पर रूपाधिकृत हुई है।

धारा 17 A. अवराधों का रूपाधिकृत करने की शक्ति - राज्य शासन शासकीय राजप5 में अधिसूचना जारी कर वन अधिकारी को निम्न के लिए अधिकृत कर सकता है -

- (a) उस व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध इन अधिनियम के या इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, उस अपराध के लिए जो उस अपराधी ने किया हो, रूपाधिकृत के रूप में राशि रूपाधिकृत करने।
- (b) जब कोई ऐसी सम्पत्ति जप्त हुई हो, जो राजसात होने के दायित्वाधीन हो, उसको राजसात होने के आदेश होने के पूर्व, समुचित अधिकारी द्वारा अनुमानित किया जावे, सम्पत्ति के मालिक द्वारा भुगतान करने पर छोड़ सकता है।
- (2) इस रूपाधिकृत राशि या मूल्य दोनों के, जैसा रूपाधिकृत हो, के भुगतान होने पर वह सन्देहाःरूपाधिकृत व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो को मुक्त किया जावेगा, और वह सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
- (3) इस धारा के अन्तर्गत उस अधिकारी को अधिकृत नहीं किया जावेगा जो वन क्षेत्रपाल के पद से निम्न पद का हो और क्लाज (a) के अन्तर्गत रूपाधिकृत के रूप में जो राशि वसूल की जावेगी वह जप्त शुदा तेन्दू पत्ते के मूल्य के दस गुना से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यदि वह तेन्दू पत्ता, जिसके सम्बन्ध में अपराध कारित हुआ है, वह शासन की सम्पत्ति नहीं है या जप्तशुदा तेन्दूपत्ते का मूल्य रू. 1000/- से कम हो, और अपराधी ने रूपाधिकृत बार अपराध किया हो, तो उस व्यक्ति को रू. या जप्तशुदा वस्तु का (तेन्दूपत्ता छोड़कर) मूल्य जमा करने पर (जो कम हो) छोड़ दिया जावेगा, और जप्तशुदा तेन्दूपत्ता यदि शासन की सम्पत्ति न हो, तो उसके मूल्य के भुगतान करने पर या अन्यथा छोड़ दिया जावेगा।

धारा 18. सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति (Saving) - किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका इस रूपाधिकृत किया जाना अभूँषित रहा हो, पहुंचाये गये या संभाव्यतः पहुंचाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या सम्भाव्यतः उठाई जाने वाली क्षति के लिए कोई वाद या अभियोजन या विधिक कार्यवाही रूपाधिकृत नहीं होगी।

धारा 19. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य शासन, पूर्व रूपाधिकृत की शक्ति के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के सामान्यतया किन्हीं भी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर रूपाधिकृत रूपाधिकृत डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समत या किन्हीं भी विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेगा, अर्थात्-

2 (क) विवलोपित,

(ख) तेन्दू पत्ते की मूल्य सूची का रूपाधिकृत,

(ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की विधि,

(घ) वे निबन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन अनुज्ञाप5 जारी किया जायेगा, वह रूपाधिकृत अधिकारी जिसके द्वारा वह रीति जिसमें तथा वह फीस या फीसें जिसकी या जिनकी देनगी की जाने पर विभिन्न रूपाधिकृत की परिवहन गाड़ियों के लिये अनुज्ञाप5 जारी किये जा सकेंगे।

(ङ) धारा 10 के अधीन पंजीयन (Registration) - की रीति,

(च) (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रिज:शेशन की रीति, कालाविध, जिसके भीतर ऐसारिज:शेशन किया जावेगा तथा उसके लिये देय फीस।

(2) धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन घोषणा का रूप। अधिकारी जिसको, दिनांक तथा रीति, जिस प्रकार घोषणा प्रस्तुत की जावेगी।

1. म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 2007 द्वारा धारा 17- A जोड़ी गई। 2. म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा विनियमित।

1(च-एक) धारा 12 (क) की उपधारा (3) के अधीन वह राशि (Consideration) जिसकी देनगी की जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी।

1(च-दो) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन वह रूप। जिसमें सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियों की सूचना भेजी जायेगी।

1(च-तीन) धारा 14-क की उपधारा (1) के अधीन वह रूप जिसमें अपील की जाएगी तथा फीस की वह रकम जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी और वह रूप जिसमें वह देय होगी।

(छ) कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त व विवक्षित (expressly) रूप से विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान-सभा के पटल पर रखे जावेंगे। टिप्पणी - धारा 19(1) मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1965 नियम (6) म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) संशोधन अध्यादेश, 1965 (संशोधन ब. 3 वर्ष 1965) की धारा 3 से किया गया है वह अवैधानिक नहीं है। राज्य शासन को राज्य सूची (खण्ड ब. 19) के अन्तर्गत अधिनियम बनाने की शक्ति है तथा ऐसे अध्यादेश के लिये राष्ट्रपति की पूर्वानुमित लेने की आवश्यकता नहीं है। (देखें AIR1966 M.P. 110)

(2) म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) 1964 की धारा 19 के अन्तर्गत बने नियम रूल 3(a) फामर् सी, यह क्लॉज 6(XX) जो उसके अन्तर्गत बने वे वैधानिक हैं और राज्य शासन की नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत हैं। (देखें भगवती बीडी ली.ज.कं.वि. म.प्र. शासन, वीकली नोट 1978(1), पृष्ठ 394)

धारा 20. भारतीय वन अधिनियम के उपबन्ध अन्य विषयों को लगाए होंगे - तेन्दू पत्तों से सम्बन्धित वे विषय जिनके लिये अधिनियम में उपबन्ध नहीं हैं और जिनके लिये उपबन्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं.

16) में है, उस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

धारा 21. निरसन - विन्ध्यदेश तेन्दू पत्ता अधिनियम, 1953 (ब. 6, वंज 1953) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 22. किठनाइयों का निवारण - इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई किठनाई उत्पन्न हो, तो राज्य शासन आदेश द्वारा ऐसे उपबन्धों से असंगत न होने वाला कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगा जो कि उसे किठनाई का निवारण करने के व्याजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

टिप्पणी - (1) उन टेन्डर में जिनमें उपरीलेखन हो (over writing) अमान्य किये जा सकते हैं। उनको संविधान की धारा 226 का लाभ नहीं मिलेगा।

(2) तेन्दू पत्ता टेन्डर की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप जमा धन राज सात नहीं हो सकता हक्यांक उससे शासन को कोई हानि नहीं हुई। निर्णय दि. 2-5-88 जबलपुर हाईकोर्ट।

(Misc. Petition No. 514/1988 & other (J.B.P.))

1. म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संशोधित।